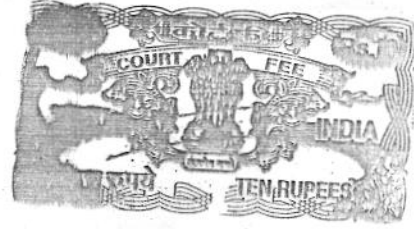


301

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर



करण क्रमांक

- दो/2012 निगरानी - 835 II / 12

मुस0 चिन्तीबाई पुत्री मुलाथमारसंह
निवासी हरपालपुर, तहसील-नौगाँव
जिला- छतरपुर — आवेदक
विरुद्ध

1- कुलदीपसिंह तनय स्व0 दाम्द्रसिंह
ठाकुर निवासी ग्राम- नाड पहाडिया,
तहसील - नौगाँव जिला-छतरपुर म.प्र.
2- मध्यप्रदेश शासन- अनावेदकगण

नायबतहसीलदार, नौगाँव द्वारा प्र0क्र0 13/अ-12/2011-12 में
पारित आदेश दिनांक 13-02-2012 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत
धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश तथा सीमांकन की कार्यवाही अवैध, अनियमित तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
- 2- यह कि, भूमि सर्वे क्रमांक 349 ग्राम- नाडपहाडिया के 1/2 भगी की आवेदक भूमिस्वामी तथा आधिपत्यधारी है. उक्त भूमि में आवेदक का अत्यन्त पुराना मकान बना है. जिसमें वह निवास करती है तथा बाकी भाग पर आवेदक का निस्तार तथा खेती है. बाकी 1/2 भाग के स्वामी राघवेन्द्र आदि है.
- 3- यह कि, आवेदक के भाग से लगे हुये भूमि सर्वे क्रमांक 306, 307 एवं 308 अनावेदक के है जिसमें अनावेदक अवैध रूप से कॉलोनी मनु भूखण्ड विक्रय कर रहा है.
- 4- यह कि, आवेदक की भूमि को हडपने के उद्देश्य से अनावेदक ने तहसील न्यायालय में सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना सीमांकन की कार्यवाही की गयी. आवेदक के सरहदी कृषक होते हुए भी उसे कोई सूचना नहीं दी गयी. तथाकथित सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होती है.
- 5- यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये तथाकथित सीमांकन के प्रतिवेदन तथा पंचनामों का अवलोकन किये बिना सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि करने में अधीनस्थ

301

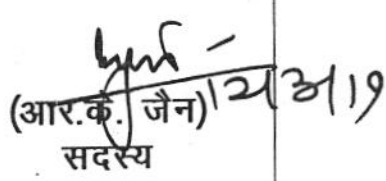
- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-835-दो / 2012

जिला-छतरपुर

मुस. चिन्टीबाई विरुद्ध कुलदीप सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदावर्तन अभिभाषक हस्ताक्षर
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. यह निगरानी नायब तहसीलदार नौगांव, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13-02-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 08-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p align="right">  (आर.क. जैन) 23/3/19 सदस्य </p>